भारत ने विदेशी एयरलाइन्स को जी.एस.टी. में बड़ी राहत दी

जी.एस.टी. काउन्सिल ने विदेशी एयरलाइन्स को सेवाओं के आयात में जी.एस.टी. से छूट प्रदान की है

- **जी.एस.टी. काउन्सिल के इस फैसले की एयरलाइन्स सैक्टर की बड़ी जीत माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि डायरैक्टोरेट जनरल ऑफ जी.एस.टी. इन्टैलिजैंस ने एयरलाइन्स सैक्टर से 39,000 करोड़ रूपए की टैक्स डिमांड की थी।**
- **जी.एस.टी. काउन्सिल की 54वीं बैठक, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की थी, में उद्योग जगत के हित में कई फैसले किए गए।**
- **काउन्सिल ने सरकारी युनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सैंटर को रिसर्च अनुदान में भी जी.एस.टी. से छूट प्रदान की, जिसे देश की रिसर्च क्षमता को प्रोत्साहन मिलेगा।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। भारत में परिचालन करने वाली विदेशी एयरलाइनों को, उनके ब्रांच ऑफिसों के माध्यम से सेवाओं के आयात पर जी.एस.टी. से छूट देने के निर्णय से एयरलाइन उद्योग ने बड़ी राहत की सांस ली है। जी.एस.टी. काउन्सिल का यह कदम एयरलाइन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रुप में आया है, खासकर, डायरैक्टोरेट जनरल ऑफ जी.एस.टी. इन्टैलिजैंस (डी.जी.जी. आई.) द्वारा लगभग 39,000 करोड़ रुपए की टैक्स डिमाण्ड लगाए जाने के बाद।

शार्दुल अमरचंद मंगलदास एण्ड कंपनी के पार्टनर रजत बोस ने कहा "एयरलाइन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए, भारत में ब्रांच ऑफिसों के माध्यम से परिचालन करने वाली विदेशी कंपनियों द्वारा देश के बाहर अपने मुख्यालय या अन्य प्रतिष्ठानों से सेवाओं के आयात पर जी.एस.टी. से छूट दी गई है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि पिछली अवधि के मुद्दों को भी नियमित किया जाएगा। इससे हाल ही में जारी कारण बताओ नोटिस पर विराम लग जाएगा, जिसमें, भारत में ब्रांच ऑफिसों के माध्यम से परिचालन करने वाली विदेशी एयरलाइनों पर लगभग 39,000 करोड़ रुपए की जी.एस.टी. मांग की गई थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई 54 वीं बैठक में, जी.एस.टी. काउन्सिल ने कई महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की, जिनका उद्योग जगत के नेताओं ने स्वागत किया। उल्लेखनीय रुप से "नमकीन" उत्पादों पर जी.एस.टी. रेट को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने कहा कि यह परिवर्तन "टैक्स ट्रीटमैंट" को स्पष्ट करता है तथा लागू दरों के बारे में पिछली अनिश्चितताओं को स्पष्ट करता है।

डैलोइट इण्डिया में पार्टनर, हरप्रीत सिंह ने स्पष्ट किया, "पफ स्नैक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली प्रक्रिया "एक्सट्रूज़न" पर पहले एच.एस.एन. एन्ट्री 1905 के तहत 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता था। उद्योग ने इन उत्पादों को एन्ट्री 2016 के तहत वर्गीकृत किया था, जिस पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता था। हाल ही में किए गए संशोधन ने इस वर्गीकरण मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए हल कर दिया है।"

जी.एस.टी. काउन्सिल गंभीर कैंसर दवाओं पर जी.एस.टी. को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है तथा धार्मिक तीर्थ यात्रियों से संबंधित हैलिकॉप्टर शेयरिंग सेवाओं के लिए जी.एस.टी. छूट की शुरुआत की।

डी.पी.एन.सी. ग्लोबल में जी.एस.टी. के प्रमुख शिवाशीष करनानी ने कहा कि इन दरों में कटौती से उपभोक्ता लागत कम होगी और परिषद द्वारा नए मंत्री समूह (जी.ओ.एम.) के माध्यम से जीवन और स्वास्थ्य बीमा के लिए कम जी.एस.टी. दरों की खोज आशाजनक है। इसकी रिपोर्ट इस वर्ष अक्टूबर तक आने की उम्मीद है।

इसके साथ ही, काउन्सिल ने सरकारी विश्वविद्यालयों रिसर्च सैंटरों को रिसर्च ग्रांट के लिए जी.एस.टी. में छूट दी, जिसका उद्देश्य भारत की अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करना है। इस बीच ऑनलाइन गेमिंग के टैक्सेशन पर चर्चा जारी है और इस बैठक में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है।

परिषद ने स्वास्थ्य बीमा पर जी.एस.टी. दरों की आगे की जांच के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। यह इस बात का संकेत है कि हैल्थ इन्श्योरैंस प्रीमियम पर जी.एस.टी. रेट घटाकर लोगों को, विशेषरुप से वरिष्ठ नागरिकों को काफी राहत दी जाएगी। वर्तमान में इन प्रीमियम्स पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केन्द्र तथा राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से 8,262.94 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम से 1,484.36 करोड़ रुपए जी.एस.टी. इकट्ठी की।

भाजपा की सदस्यता 8 दिन में दो करोड़ के पार हुई

नयी दिल्ली, 10 सितंबर (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के आठ दिन में सदस्यों की संख्या दो करोड़ से अधिक हो गई है।

पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष ने उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान इन नौ प्रदेशों में सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए अलग-अलग बैठकें कीं जिनमें प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, सदस्यता प्रमुख, सदस्यता टोली के पदाधिकारी शामिल हुए।

बैठक के बाद पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने आज शाम यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि

- **भाजपा के तमाम नेता इन दिनों सदस्यता अभियान को सफल बनाने में जुटे हुये हैं।**

भाजपा के संगठन पर्व के तहत 02 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी का प्रथम सदस्य बन कर भाजपा के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया था। महज आठ दिन में सदस्यता अभियान के तहत भाजपा की सदस्यता संख्या दो करोड़ को पार कर गई है। तावड़े ने कहा कि इसी सदस्यता अभियान के संदर्भ में मंगलवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह एवं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष ने नौ प्रदेशों के साथ अलग-अलग बैठक कर सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इन बैठकों में उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, सदस्यता प्रमुख, सदस्यता टोली के पदाधिकारी शामिल हुए।

मार्बल उद्योग की बदहाली के लिये अशोक गहलोत जिम्मेदार- सुनील भार्गव

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील भार्गव ने गहलोत की "एक्स" पर टिप्पणी का करारा जवाब दिया

जयपुर, 10 सितम्बर। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सुनील भार्गव ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। भार्गव ने सोशल मीडिया एप "एक्स" पर अशोक गहलोत की पोस्ट पर लिखा कि, "पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 15 साल तक राजस्थान में शासन किया था। यह निराशाजनक है कि वह तथ्यों की जांच किए बिना तुच्छ राजनीति में लगे हुए हैं। वर्तमान में राजस्थान का मार्बल उद्योग जिन समस्याओं से जूझ रहा है, वह उनके (गहलोत के) ही कुशासन की भव्य विरासत है।"

दरअसल अशोक गहलोत ने मंगलवार को सोशल मीडिया एप 'एक्स" पर पोस्ट कर लिखा था कि "यह

- **सुनील भार्गव ने लिखा कि गहलोत तथ्यों की जाँच किये बिना तुच्छ राजनीति करने में लगे हैं।**

बेहद दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्रीजी विदेश जाकर वहां के उद्यमियों से राजस्थान में आकर निवेश करने की बात कर रहे हैं, पर राजस्थान के मार्बल-ग्रेनाइट उद्यमियों की मांगों को प्रदेश की भाजपा सरकार, केन्द्र के सामने क्यों नहीं रख रही है। सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश के उद्यमी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि राजस्थान की वित्त मंत्री ने दिल्ली में होने के बावजूद जी.एस.टी. काउंसिल में भाग क्यों नहीं लिया? यह दिखाता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।"

अशोक गहलोत की इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए सुनील भार्गव ने राजस्थान के मार्बल उद्योग की बदहाली के लिए अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि गहलोत सिर्फ तुच्छ राजनीति करने में लगे हैं, उन्होंने राजस्थान में 15 वर्ष तक बतौर मुख्यमंत्री राज किया, लेकिन कभी भी मार्बल-ग्रेनाइट उद्यमियों की चिंता सरकार में रहते हुए नहीं की। भार्गव ने कहा कि गहलोत अपनी पार्टी की चिन्ता करें, जो लगातार टूट रही है। भाजपा की चिन्ता हमारा नेतृत्व कर लेगा।

गृहिणी की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मजदूरी दर से मुआवजा राशि की गणना की जाएगी। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरि ओम अत्री ने बताया कि नई गाइड लाइन में स्थाई निशक्तता को लेकर पूर्व में निशक्तता के प्रतिशत पर मिलने वाली प्रति प्रतिशत राशि को भी दस हजार रुपए से बढ़ाकर बीस हजार रुपए किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती गाइड लाइन में सभी प्रकार की शारीरिक क्षति को शामिल नहीं किया गया था। नई गाइड लाइन में अस्थि भंग के लगभग सभी मामलों को शामिल कर विस्तृत श्रेणियों की सिफारिश की गई है।

कोरियन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, और राजस्थान सरकार के अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं।

उदयपुर वाणिज्य कर विभाग का संयुक्त आयुक्त 8 लाख रू. की रिश्वत लेते गिरफ्तार

- **आरोपी रविन्द्र जैन के मकान व अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है।**
- **जैन ने जी.एस.टी. कार्यवाही नहीं करने और आई.टी.सी. क्लेम का फायदा देने के एवज में परिवादी से आठ लाख रूपए रिश्वत मांगी थी।**

उदयपुर, 10 सितम्बर (कासं)। एन्टी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) उदयपुर इंटेलिजेंस इकाई ने जी.एस.टी. कार्यवाही नहीं कर आई.टी.सी. क्लेम का फायदा देने के एवज में पीड़ित से आठ लाख रूपये की रिश्वत मांगने के मामले में वाणिज्य कर विभाग उदयपुर के संयुक्त आयुक्त रविन्द्र जैन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉ. रवीप्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इंटेलिजेंस इकाई को परिवादी ने शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि रिसॉर्ट का जी.एस.टी. टीम द्वारा किए गए सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही नहीं कर आईटीसी क्लेम का फायदा करवाने की एवज में वाणिज्य कर विभाग उदयपुर के संयुक्त आयुक्त रविन्द्र जैन द्वारा 8 लाख रूपये रिश्वत मांग कर उसे परेशान किया जा रहा है। इस पर ए.सी.बी. उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरविज़न में ए.सी.बी. उदयपुर इंटेलिजेंस इकाई की पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन कर ट्रैप कार्यवाही की। कार्रवाई के दौरान आरोपी रविन्द्र जैन को 8 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो की टीम इस मामले में विभाग के अन्य अधिकारी, कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है। वहीं, आरोपी के आवास व अन्य ठिकानों की तलाश की जा रही है।

नाबालिग से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बोलने गई थी। इस दौरान विक्रम उसे जबरन अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत में घटना दोहराते हुए दुष्कर्म की बात कही। इसके अलावा चिकित्सीय परीक्षण में भी आया कि उसके साथ जबरन संबंध बनाए गए हैं। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

फोन टेपिंग प्रकरण में केस वापस लेने की अनुमति

जयपुर, 10 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़े फोन टेपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पेश केस को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश राज्य सरकार की ओर से केस को वापस लेने के संबंध एफ.आई.आर. की जांच और अभियोजन का अधिकार राज्य सरकार को है। इसलिए इसकी जांच राजस्थान पुलिस को करनी चाहिए। इसलिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए केस को राजस्थान पुलिस के पास भेजा जाना चाहिए। इस मामले में गत पांच फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने

- **सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के खिलाफ दायर केस वापस लेने की अनुमति दे दी है। यह केस पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दायर किया था और मौजूदा भाजपा सरकार केस वापस ले रही है।**

में दायर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि गजेन्द्र सिंह के खिलाफ मौजूदा मामले में कोई मैरिट नहीं है। ऐसे में केस को वापस लेने की अनुमति दी जाए। केस में कहा गया था कि मामले में क्राइम ब्रांच की ओर से दर्ज सुप्रीम कोर्ट से इस मूल केस को जारी रखने या नहीं रखने को लेकर समय मांगा था। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने ए.ए.जी. शिवमंगल शर्मा से चर्चा सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार के खिलाफ, दायर इस केस को वापस लेने का निर्णय लिया था।

'राहुल के खरे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सम्मान तथा विनम्रता लाने का तथा इस विचार को पोषित और प्रोत्साहित करने का है कि भारत एक ऐसा देश है, जहाँ अनेक प्रकार के विचारों तथा पहचानों का सह-अस्तित्व है। भाजपा-आर.एस.एस. इस समावेशिता के लिए एकमात्र और सबसे बड़ा खतरा हैं।"

वेणुगोपाल ने कहा, "राहुल जी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयानों के बारे में शिकायत करना भी भाजपा का दोहरा पाखंड है। जब मोदी अपनी इस घिसी-पिटी बात को दोहराने का एक भी मौका नहीं चूकते कि "2014 से पहले के 60 वर्षों में (भारत में) कुछ भी नहीं हुआ।" यह भारतीयों की उन कई पीढ़ियों, जिन्होंने इस देश को महान बनाया, का सचमुच ही अपमान है।"

उन्होंने कहा कि जब भाजपा को आईना दिखा दिया गया है तो वह, निरर्थक आक्रोश में आने के बजाय, अपनी आलोचना को सृजनात्मक रूप में ले।

अडानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और "कॉस्ट इफैक्टिव" तथा पारदर्शी बुनियादी ढांचों के समझौतों की आवश्यकता पर जोर दे रही है।

'सेबी प्रमुख की एग्रो कंपनी के बारे में जवाब दें मोदी'

कांग्रेस ने सवाल किया है कि माधबी बुच ने सेबी के अपने कार्यकाल में रहते हुए एग्रो कंपनी के माध्यम से 2 करोड़ 95 लाख रुपए कमाए

नयी दिल्ली, 10 सितंबर (वार्ता) कांग्रेस ने कहा है कि सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच तथा उनके पति की कंपनी का खुलासा हिंडन वर्ग रिपोर्ट में हुआ है जिसका श्रीमती बुच ने खंडन किया है लेकिन इसको लेकर जो रिपोर्ट में सामने आई हैं वह चौंकाने वाली है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस प्रचार तथा संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि "हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एक कंपनी एग्रो एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड का नाम सामने आया था जो कि 7 मई 2013 में रजिस्टर हुई थी। यह कंपनी माधबी पुरी बुच और उनके पति की है लेकिन श्रीमती पुरी ने रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खंडन किया था। खंडन में उन्होंने लिखा कि जबसे श्रीमती पुरी सेबी में गई तब से यह कंपनी निष्क्रिय है। लेकिन इस कंपनी में अभी भी 99 प्रतिशत हिस्सेदारी माधबी जी की है।"

प्रवक्ता ने सरकार से सवाल किया और कहा "एग्रो से किन-किन कंपनियों ने सेवाएं लीं। जिन कंपनियों ने एग्रो की सेवाएं लीं क्या वे सेबी के स्कैनर में हैं। इसका जवाब हमें मिला कि माधबी जी ने सेबी के अपने कार्यकाल में रहते हुए एग्रो के माध्यम से 2 करोड़ 95 लाख रुपए कमाए।"

उन्होंने मोदी से पूछा "क्या आपको पता था कि एग्रो में माधबी जी की 99 प्रतिशत शेयर होल्डिंग है। जब आपने माधबी जी को सेबी चेयरपर्सन बनाया, तो क्या आपको किसी एजेंसी ने रिपोर्ट नहीं दी थी। क्या आपको जांच एजेंसियों ने नहीं बताया था कि एग्रो के आर्थिक-व्यावसायिक रिश्ते उन कंपनियों से हैं, जिनकी जांच सेबी कर रही है। क्या आपके सामने किसी ने भी माधबी जी के खिलाफ सबूत नहीं रखे थे कि इन्हें दूसरे कंपनियों से इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं।"

शिंदे को गृह मंत्री रहते श्रीनगर के लाल चौक जाने में लगता था डर

नयी दिल्ली 10 सितंबर (वार्ता) कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे को गृह मंत्री रहते हुये जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के लाल चौक और डल झील पर जाने में डर लगता था। शिंदे ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्हें श्रीनगर के लाल चौक तथा डल झील के पास जाने में डर लगता था। उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीरी पंडित विजय धर की सलाह पर मैं वहां गया और लोगों से मिला, उनसे बात की। उस समय उनकी सलाह से मुझे बहुत प्रसिद्धि मिली। लोगों में संदेश गया कि एक ऐसा गृहमंत्री है, जो बिना डर के श्रीनगर जाता है, लेकिन मैं ही जानता हूं, कि उस समय मेरी क्या हालत थी, किसको बताऊं मैं...। शिंदे सोमवार रात यहां अपनी आत्मकथा 'फाइव डिकेड इन पॉलिटिक्स' के विमोचन के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।

वॉशिंगटन की युनिवर्सिटी में राहुल के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मंत्री ने आगे कहा, "पिछले दिन उन्होंने कहा, (भारत) बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहाँ कोई रोज़गार नहीं है। कभी वे कुछ और कहते हैं। वे आर.एस.एस. की भारी निंदा करते हैं। यह सब इसलिये और ज्यादा बुरा है क्योंकि वे वहाँ विपक्ष के नेता के रूप में गये हैं, सामान्य नागरिक के रूप में नहीं।"

राहुल की दादी तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंग रक्षकों द्वारा की गई हत्या के बाद के 1984 के सिख-विरोधी दंगों का जिक्र करते हुये, पुरी ने कहा कि भारत के सिखों के सामने केवल एक बार "अस्तित्व का खतरा पैदा हुआ था और समय गांधी परिवार सता में था।"

भाजपा नेता ने कहा, "मैं पिछले छः दशक से ज्यादा समय से पगड़ी तथा कड़ा पहनता आ रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने कभी कोई समस्या नहीं आई, एक समुदाय के रूप में केवल एक बार, हमें अपने अस्तित्व के लिए खतरा महसूस हुआ था और यह वो समय था, जब राहुल गांधी का परिवार सत्ता में था।"

उन्होंने आगे कहा, "1984 में, सिखों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था। तब 3000 निर्दोष लोग मारे गये थे। वे घरों से घसीटते हुये बाहर लाये गये थे, उनके चारों ओर टायर रखे गये थे तथा वे जीवित जला दिये गये थे।

पुरी के अलावा, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने भी राहुल गांधी द्वारा बेरोज़गारी तथा आर.एस.एस. पर की गई टिप्पणियों को लेकर, उन पर जमकर प्रहार किये।

राहुल ने कहा, "देखिये, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लड़ाई किस बात को लेकर है। लड़ाई राजनीति को लेकर नहीं है। लड़ाई बाहरी और ऊपरी चीजों को लेकर है। आपका नाम क्या है, (उन्होंने श्रोताओं में बैठे एक व्यक्ति से उसका नाम पूछा तथा उसने बताया, मालेन्द्र सिंह) लड़ाई इस बात को लेकर है कि एक सिख होने के नाते, वह भारत में पगड़ी पहनेगा, एक सिख के रूप में, वह भारत में कड़ा पहनेगा, सिख होने के नाते, वह गुरुद्वारे जायेगा, लड़ाई इस चीज़ को लेकर है, यह केवल उसी के लिये नहीं है, सभी धर्मों (के लोगों) के लिये है। लड़ाई इस बारे में भी है। मुझे इस भीड़ में बहुत सारे लोग तमिलनाडू के, पंजाब के, हरियाणा के, तेलंगाना के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं। मैं सब लोगों को देख सकता हूँ।"

कांग्रेस नेता ने देश में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को रेखांकित करते हुये कहा, "देखिये, जब मैं कहता हूँ "केरल" जहां से मैं सांसद रहा हूँ। तो जब मैं केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कहता हूँ तथा अगर आप इन चीज़ों को समझते नहीं हैं तो आप कहते हैं, केरल मात्र एक शब्द है पंजाब मात्र एक शब्द है, लेकिन ये सामान्य शब्द मात्र नहीं हैं। ये आपका इतिहास है, आपकी भाषा है, आपकी परम्परा है, आपकी पूरी की पूरी कल्पना इन शब्दों में निहित हैं और आर.एस.एस. मूलरूप से यह कह रही है कि कुछ राज्य, कुछ अन्य राज्यों से कमतर हैं, कुछ भाषाएं, कुछ अन्य भाषाओं से कम महत्वपूर्ण हैं, कुछ धर्म, कुछ अन्य धर्मों से घटिया हैं, कुछ समुदाय कुछ अन्य समुदायों से निम्नतर हैं, लड़ाई ऐसी चीज़ों को लेकर है।"

'जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन भाजपा नेताओं ने ही करवाया था'

नई दिल्ली, 10 सितंबर। कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया ने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों को लेकर बड़ा दावा किया है। हाल ही में एक अखबार से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही उन्हें वहां विरोध प्रदर्शन की अनुमति दिलाई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता ही अपनी पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे थे। हाल ही में पूनिया और पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थामा है। फोगाट जुलाना सीट से मैदान में हैं।

ट्रिब्यून से बातचीत में पूनिया ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनों को कांग्रेस की साजिश होने से इनकार किया है। उन्होंने

- **कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया ने कहा, भाजपा नेता ही अपनी पार्टी के खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए थे।**

कहा, मेरे दावों को साबित करने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड भी हैं। आरोपों के विपरीत कि पहलवानों के प्रदर्शनों के पीछे कांग्रेस ही थी, इसके पीछे भाजपा नेता थे जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे थे।

उनके दो नेताओं ने उस जगह पर विरोध प्रदर्शन के लिए हमें अनुमति दिलाई थी।

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को लेकर उन्होंने कहा, अब वह हमारे लिए अप्रासंगिक हैं। हां, पहलवानों के साथ जो भी जंतर मंतर पर हुआ, वो राज्य और देश में बड़ा चुनावी मुद्दा है, क्योंकि हर घर में हमारी बहनें और बेटियां हैं।

ममता बनर्जी आंदोलनरत डॉक्टरों का डेढ़ घंटे इंतजार करती रह गईं

ममता बनर्जी सरकार की तरफ से ईमेल भेजकर आंदोलनकारी डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया गया था

- **यह ईमेल बंगाल सरकार स्वास्थ्य सचिव की ओर से भेजा गया था जिनकी गिरफ्तारी की आंदोलकारी डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं।**
- **पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के बैनर तले डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री को अपनी पाँच माँगें मानने के लिए मंगलवार शाम पांच बजे तक का अल्टीमेटम दिया था जिसमें शहर के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को बर्खास्त करना , स्वास्थ्य सचिव और उनके दो डिप्टी - स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख का इस्तीफा मांगा गया था तथा 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधियों की पहचान करना आदि प्रमुख मांगें थी।**

कोलकाता, 10 सितंबर (वार्ता) पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मंगलवार शाम को कहा कि आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों ने अपनी शिकायतों और मांगों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत के लिए सरकार की ओर से भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया।

जूनियर डाक्टरों ने राज्य स्वास्थ्य सचिवालय तक रैली निकाली और उसके सामने धरना-प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने ईमेल को "अपमानजनक" करार दिया। यह ईमेल स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम द्वारा भेजा गया था जिनके इस्तीफे की डाक्टरों ने मांग की है।

सुश्री भट्टाचार्य ने राज्य सचिवालय नबन्ना में संवाददाताओं से कहा कि ईमेल शाम 6:10 बजे भेजा गया था जिसमें विवादास्पद मुद्दों पर बातचीत के लिए आंदोलनकारी डॉक्टरों के दस और प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शाम साढ़े सात बजे तक अपने कक्ष में इंतजार करती रहीं और फिर चली गईं।

उन्होंने कहा "लेकिन हमें डॉक्टरों से कोई जवाब नहीं मिला और मुख्यमंत्री शाम 7:30 बजे नबन्ना से चली गयी।" उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जूनियर डॉक्टरों को मंगलवार शाम पांच बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया लेकिन मुख्यमंत्री ने उनके मुद्दों और मांगों को सुनने के लिए शाम 7-30 बजे तक इंतजार किया।

आंदोलनकारी डॉक्टरों ने तर्क दिया कि ईमेल राज्य के स्वास्थ्य सचिव की आईडी से भेजा गया था जिनके इस्तीफे की मांग उन मांगों में से एक थी जिसके लिए वे सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।

चिकित्सक देबाशीष हलदर ने कहा, "हमने इस महीने की शुरुआत में अपने लालबाजार (शहर पुलिस मुख्यालय) मार्च के दौरान कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को उनके इस्तीफे की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपने के बाद भी अब तक कुछ नहीं हुआ है।"

उन्होंने कहा कि शहर के पुलिस आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया था कि यदि सर्वोच्च अधिकारी (सीएम) उन्हें पद छोड़ने का निर्देश देंगी तो वह ऐसा करेंगे।

डॉक्टर ने बताया "कल मुख्यमंत्री ने नबन्ना में कहा कि पुलिस आयुक्त ने कई बार इस्तीफे की पेशकश की थी लेकिन वे सहमत नहीं हुईं।"

डॉक्टरों ने कहा "ईमेल हमारे लिए भी अपमानजनक है क्योंकि इसे केवल "सर" को संबोधित किया गया था जबकि आंदोलन में सैकड़ों मैडम शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि ईमेल में उल्लेख किया गया था कि "10 से अधिक डॉक्टर" मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं और यह उनके लिए अपमानजनक भी था। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी पांच सूत्री मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा।

हालाँकि पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के बैनर तले डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री को अपनी पाँच माँगें मानने के लिए मंगलवार शाम पांच बजे तक का अल्टीमेटम दिया था जिसमें शहर के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को बर्खास्त करना , स्वास्थ्य सचिव और उनके दो डिप्टी - स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख का इस्तीफा , 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधियों की पहचान करना और उन्हें गिरफ्तार करना और उन्हें सजा देना , कार्य का सुरक्षित और संरक्षित स्थान और अस्पतालों में अनुकूल माहौल की बहाली भी शामिल था।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में गत नौ अगस्त को महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद से मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों का काम बंद आंदोलन 33वें दिन में प्रवेश कर गया है।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाइन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908